



विकास का मॉडल और समकालीन कविता में भारतीय किसान

डॉ. कृष्ण कुमार
 शहीद उद्धम सिंह राजकीय महाविद्यालय
 मटक माजरी(इन्ड्री) जिला. करनाल (हरियाणा)

प्रस्तावना :

भारत मूलतः किसानों का देश है। इसकी पचास प्रतिशत से ऊपर आजादी किसी ना किसी रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। यह व्यवसाय उनकी आवश्यकता भी है, पहचान भी है और मजबूरी भी लगभग 1 अरब 27 करोड़ आजादी का पेट भरने का दायित्व और विकास की अंतिम कतार में खड़ा भारतीय किसान यदि आत्महत्या करने को मजबूर होता है। तो बुद्धिजीवियों का दायित्व बनता है कि उन परिस्थितियों का अध्ययन करें, उस यथार्थ के परदों को खोलकर देखें जिससे देश में इतना बोझिल और निमं मवातवरण तैयार हुआ। उसने अपनी समस्त संभावनाओं को चुका हुआ मान लिया। मैनेजर पांण्डेय ने कहा था – भारत में किसान और कृषि गहरे संकट में है। किसानों के संकट के गंभीरता का प्रमाण उनकी आत्महत्याओं की संख्या से मिलता है। कृषि के संकट होने का सबुत यह है कि बड़ी संख्या में किसान अब खेती से मुह मोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं।¹ समकालीन कविता में किसानों का जीवन के प्रति मोहभग की उत्तरदायी परिस्थितियों का चित्रण गहराई से हुआ है।

समकालीन कविता की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उस वैश्विक परिघटना को जानना समझना जरुरी है जो कई दशकों से हमारे युग और राष्ट्र पर दबाव डाल रही है। सैद्वान्तिक रूप से देखें तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका में पूंजी का नया केन्द्र पनप रहा था तथा व्यवाहारिक दृष्टि से सातवें आठवें, नौवें दशक में यहीं पूंजी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष विकासशील देशों पर अपना दबाव बनाकर अपना ऐंजडा लागू करवाने में सफल रही। सरकारों की प्राथमिकताएं बदली। राष्ट्रीय अनुकूल सामाजिक सरकारों को बाजारोन्तुख सुधारों की ओर मोड़ दिया। बाजार का जादू कुछ इस कदर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगा कि हम हर नीतिगत फैसला लेने से पहले बाजार और पूंजी के मिजाज को समझने लगे, उसका अध्ययन करने लगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पूंजी प्रमुख हो गई और लोग हाशिए पर जाने लगे। हमने इस विकास के मॉडल को अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण स्वीकार किया, न कि अपनी

आवश्यकताओं के कारण। ब्रह्मोदव शर्मा का कथन है कि “आजादी के बाद सवाल था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश के नवनिर्माण का। ऐसी स्थिति में भारत का आजाद सरकार ने उद्योग को इस देश की अर्थव्यवस्था का लिडिंग सैक्टर घोषित कर दिया। इसे एक विडब्बना ही कहा जाएगा कि जिस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या खेती करती है उस देश की अर्थव्यवस्था का इंजन उद्योगों को माना गया।”² इसलिए इसके मनोवांछित परिणाम नहीं मिले। असद जैदी इन दशकों का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं:–

कुछ होना था सतर के दशक में जो नहीं हुआ
 अस्सी के दशक में चलने लगी उल्टी सीधी हवाएं।
 नब्बे के दशक में जो नहीं होना था, हो ही गया।
 रुखसत हा चली है पूरी सदी।
 अब यह सब अध्ययन की वस्तु है।

समकालीन कविता का मिसाज उस समय बदलना शुरू हुआ, जब 24 जुलाई 1991 को भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार पूंजी के लिए खोल दिए गए। नव उदार बाढ़ी नीतियों के गीत गाये जाने लगे। राजनेताओं और नौकरशाहों ने देश की समस्त समस्याओं का निदान आर्थिक स्वृद्धि का बढ़ना मान लिया। इस प्रक्रिया से अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ने लगी अधिकांश जनता जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए तरसने लगी। कर्ज में डूबे भारत को एकाएक सुपर पावर और आर्थिक महाशक्ति कहकर पुकारा जाने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग ऐंजसियों ने भारतीय साख को बढ़ा दिया और उम्मीद जताई कि 2030 तक अबल स्थान हासिल कर लेगी।

लेकिन जरुरी नहीं जो राजनेताओं / उद्योगपतियों का सच हो, वह जनता के लिए भी हकीकत हो। कवि अपने ढंग से युग की समीक्षा करता हुआ, आवरण में छिपे हुए सत्य को जनता के सामने बेनकाब करता है। पंकज सिंह के शब्दों में

प्रकाश और धूधलके के कितन परदों
 कितने रहस्यों में लिपटा होता है यार्थ
 कई तरह से देखना होता है
 कि कुछ कहने से पहले दिखता है
 गौर से देखो, कि उसका कोई हिस्सा
 धुएं के धूल में हाहाकार में
 भाषा के छल में जयकार में
 बाजार की तकरार में छिपा रह जाता है।

इस तरह श्रीधर करुणानिधि शाईनिंग इंडिया के हकीकत पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं।

हद से ज्यादा अच्छा लगे कुछ
 तो उसे रोको वहीं
 करो उसकी पड़ताल
 हो सकता है जो चीज दिखती है
 वह सच बिलकुल ना हो।

भूमण्डलीकरण अपनी सैद्वान्तिकी चमक-दमक शब्दों में प्रस्तुत करता है व झूठ पर सच का आवरण चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। यह बड़ा गहरा विरोधाभास है कि जिस देश की जी ० डी ० पी ० पिछले 15 वर्षों से ९ प्रतिशत अंक के आस-पास धूम रही हो। वहां लाखों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो। सुरेश सेन निशांत उस तिकड़म को बेनकाब करते हैं

जो भारतीय किसानों को लगातार विस्थापित कर रही है। प्राकृतिक स्थितियां अनुकूल होने पर लोग अपना घर—बार छोड़ने को क्यों मजबूर है। वो पड़ताल करते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगमों ने भूमण्डलीकरण की नीतियों की आड़ में उनके बीजों पर नियंत्रण कर लिया है। डब्ल्यू टी० ओ० ने ट्रिप्स (व्यापार संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार समझौता) के तहत बीजों को बौद्धिक सम्पदा घोषित करके इनके आदान—प्रदान पर रोक लगाने की व्यवस्था की है।³ अब उनके खेतों की बारी है। बहुराष्ट्रीय निगम बीजों के माध्यम से किस प्रकार उनको उनकी जड़ों से विस्थापित कर रही है, इसका नमूना निशांत की कविता में देखने को मिलता है:—

हरसूद नहीं है हमारा गांव
किसी पानी में भी नहीं डूब रहा
पर विस्थापन है कि नहीं रुक रहा
आज भी निकला यहा एक कुनबा
दूर मैदानों की ओर
बारिश भी वक्त पर हुई थी।
ठीक ढंग से जोती गई जमीन
फसलों को न नील गायों ने चरा
और न जंगली सुअरों ने उजाड़ा
फिर भी बंजर है जमीन
पता नहीं किसने बाटे थे
वे धोखेबाज बीज
जो खेतों में नमी और खाद पानी होने के
बावजूद उगे नहीं
है कोई जो कर रहा है
लोगों को दर—बदर
पर उंगली भी नहीं उठ रही उसकी ओर

बलराज लिखते हैं — ‘भूमण्डलीकृत उदारीकरण ने किसानों को उदारीकरण के जाल में कुछ ऐसे फास लिया है कि बीज, सिंचाई और खेती के औजारों के लिए लिया गया कर्ज उनके गले की फांस बनने लगा है और देखते ही देखते लाखों किसान आत्महत्या करने लगे।’⁴ कवि का यह सामाजिक सरोकार है कि उन शक्तियों की हकीकत जनता के बीच लेकर जाये, जो विज्ञापन की चमक—दमक में किसानों को स्वच्छ भाग दिखलाती है, जिसकी परिणति खेतों के प्रति मोह भंग और अन्ततः विस्थापन एवं आत्महत्या में होती है। कवि शैलेय भी ‘भंवर खाता कुम्हार और रुई हो गये कपास’ में किसान की इस सच्चाई को दिखलाते हैं :—

पर आज जब मैं
कपास के खेतों में गया
तो कांप कर रह गया
कपास उगाने वाले
रुई हो रहे थे

पंचसितारा होटल की मखमली रजाई में जाड़ों की रात बिताने वाले, वैश्विक पूँजी से याराना रखने वाले वर्ग के पास सौचने का समय नहीं है कि विदर्भ का क्षेत्र जहां बी० टी० बीजों के रोपने से आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया। यह बहुत बड़ी समस्या है, गहरे मंथन और विश्लेषण की आवश्यकता है लेकिन सताधारी वर्ग की चिंता पूँजी निवेश के लिए नयी—नयी योजनाएं बनाने कि है। इस पूँजी का गरीब—गुरवे तक तो एक अंश ही पहुंच पाता है, या तो बिचौलियों में बट जाती है या फिर निवेशकों की आकांक्षों का पूरा करती है। राजीव कुमार त्रिगर्ती लिखते हैं :—

लिखे जाने से ज्यादा जरूरी है पढ़ा जाना
जो जमीन से पैदा नहीं हुआ
वह नहीं जानता जमीन का दर्द
उसे नहीं मालूम जमीन का कष्ट
एयर कंडीशन कमरों में बनाई जाती है
किसान के विकास की योजनाएं
सब कुछ पहुंच जायेगा गांव में
इतने लुटेरे हैं जो
कितनों के तन पर
नहीं लिपटने देते कपड़ा
और पेट में नहीं जाने देते
एक भी दाना

हवा को पीना और उसमें जीना कितना मुश्किल होता है

लिखे जाने से जरुरी है इस पढ़ा जाना
उन चेहरों को जो हवा को मजबूरी में जीते हैं।

पेटेंट कानूनों की आड़ में विकसित देश, विकासशील देशों की स्थानीय प्राकृतिक संपदा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे। वे यहां की फसलों और प्राकृतिक जड़ी-बूटियों पर अधिकार जमा रहे हैं। दुनिया का 91 प्रतिशत चावल एशिया में पैदा होता है लेकिन बहुराष्ट्रीय दिवस कम्पनी सिनजेटा ने 2004 में चावल पर पेटेंट कराने की कौशिश की। भगवत रावत साम्राज्यवादी शक्तियों के इस धिनौने खेल की शातिर चालों को एक-एक करके हमारे सामने लाते हैं:-

तुम्हारे सिरहाने एक अजनबी सौदागर
रख गया है एक अनुबंध पत्र
कितने समझौते करागे तुम
वे तुम्हारे पाखरों से
उठा ले जाएंगे गुलाब आंखों वाली मछलियां
वे फांस ले जाएंगे, सबसे मीठा गाने वाली चिड़िया
फिर एक दिन तुम्हे अपने हाथ को
साबित करना पड़ेगा अपना हाथ
अपनी आंख को अपनी आंख
क्या तुम्हे खेतों की ओर चले आते
विशालकाय जूतों के निशान दिखाई देता है?

कवि अपने युग का समीक्षा और सम्भावनाओं पर विचार करता है। समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर भगवतरावत, अष्टभुजा शुक्ल, रामाज्ञाशशीधर, असद जैदी, पाश, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, निर्मला पुतल, रामतलंग, लीलाधर मंडलोइ, विष्णुनागर, कुमार अम्बुज, वीरेन डंगवाल, अरुण कमल, झानेन्द्रपति, नितन्द्र श्रीवास्तव, निदानवाज, सुरेश सेन, निशांत, कुमार विकल लीलाधर मंडलाई, विष्णु नगर, कुमार अम्बुज, वीरेन डंगवान, अरुण कमल आदि कवियों ने उदारीकरण द्वारा संचालित विकास के मॉडल के निचे छिपी किसानों की चीखों को बेनकाब किया है। इस मॉडल का उद्देश्य अधिकांश जनता को हाशेय पर धकेल कर मुठीभर लोगों के लिए सुख सुविधाओं का निर्माण करना है।

निष्कर्ष

भूमण्डलीकरण की नीतियां अपनाने के बाद, औद्योगिक घरानों में जल, जंगल और जमीन को लेकर प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ दिखाई दे रही है। इस दौड़ में वह जीत सकता है, जिसके पास अकृत संपत्ति है। यहां स्वतंत्रता के मायने किसान और औद्योगिक जगत के लिए बदल गए हैं। हमारी जी0 डी0 पी0 पिछले 15 वर्षों से 5 प्रतिशत से लेकर 9 प्रतिशत तक रही (अमेरिका, जापान और यूरोप की जीडीपी जीरो से लेकर के तीन-चार प्रतिशत तक रही है) सरकार शाईनिंग इंडिया का प्रसार करती है, दुनिया भारत को उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रहा है, लेकिन इसी दौरान लगभग 4-5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी जमीन पर पकड़ लगातार ढीली होती जा रही है। उनकी जोत का आकार कम हो रहा है। जब एक कंपनी पर कर्ज बढ़ता है तो बेलआउट पैकेज का शोर मचाया जाता है। उद्योगपति, मीडियाकर्मी, अर्थशास्त्री, वित्तीय एजेंसियां मिलकर इस प्रकार वातावरण (आकड़ों के माध्यम से) रखते हैं कि यदि जल्दी से जल्दी पैकेज नहीं दिया गया, तो निवेश पर दुरा असर पड़ेगा और जब कर्ज से दबकर किसान आत्महत्या करता है, वह सामान्य सी खबर भी नहीं बनती है। हम समकालीन हिन्दी कविता के मिजाज को समझे कि शाईनिंग इंडिया के नीचे दबी भारतीय किसान की सच्चाई को कितना समझ पाई है। हिन्दी कविता सरोकार रहने वाले कवि, पाठक और आलोचक मौजूदा विकास के मॉडल किस दृष्टि से देखते हैं। बहुधा संसार में राष्ट्र के प्रतिनिधियों की सोच एवं दृष्टि तथा रंगाकर्मियों—कलाकारों विचारों की दृष्टि में बहुत अंतर देखने को मिलता है।

सन्दर्भ ग्रन्थः-

1. मैनेजर पाण्डेय, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परम्परा, पृ0 144
2. ब्रह्मादेव शर्मा, किसानों का शोषण, हिन्दी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं जयनारायण, कल के लिए, अंक 47, सितम्बर 2004, पृ0 41
3. सम्पादक पी0 रवि, कविता का वर्तमान, पृ0 42
4. बलराम, दैनिक ट्रिब्यून, लेख – किसानों के बेबस जीवन की फांस दिनांक 19.06.2006